वर्ष–13 //अंक–9// मार्च // 2025

ISSN 2454–5805

आम आदमी पत्रिका

एक आम इंसान की सोच

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

बजट 2025-26

ज्ञान से गति की ओर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ऐतिहासिक पहल छत्तीसगढ़ की जनता बनी महाकुंभ की साक्षी

जब PM मोदी ने शेर के शावकों के साथ बिताये पल और पिलाया दूध

→12

चैम्पियनों के चैम्पियन

→22

छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति

→28

छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाषा....

सीएम बोले- अंतस को सींचती है, आत्मा को एक दूसरे से जोड़ती है

प्रगति पथ पर छत्तीसगढ़

देश में धान की सर्वाधिक किस्मों वाला राज्य

प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में देश का सबसे संपन्न राज्य

जैव विविधता के साथ हरियाली में अग्रणीय राज्य

कोयला उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य

देश के कुल सीमेंट उत्पादन में 20% का योगदान देने वाला राज्य

लौह अयस्क उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य

देश में टीन धातु का नंबर वन उत्पादक राज्य

सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश का पावरहाउस

सुशासन से समृद्धि की ओर

ChhattisgarhCMO | DPRChhattisgarh | www.dprcg.gov.in

QR स्कैन करें

RO No: 13178/9

आम आदमी पत्रिका

वर्ष–13 //अंक–9// मार्च //2025

प्रबंध संपादक : उमेश के बंसी

सर्कुलेशन इंचार्ज : प्रकाश बंसी

रिपोर्टर : नेहा श्रीवास्तव

कंटेंट राईटर : प्रशांत पारीक

क्रिएटिव डिजाइनर : जितेन्द्र साहू

मैग्ज़ीन डिज़ाइनर : मयंक पवार

एडमिनिस्ट्रेशन : कुसुम श्रीवास्तव

अकाउंट असिस्टेंट : हितेश प्रेमानी

ऑफिस कॉर्डिनेटर : योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

54/111, सालासर बालाजी मंदिर के पास,
अग्रसेन धाम के पीछे, वी.आई.पी.रोड, रायपुर (छ.ग.)

फोन : 0771-4044047

ईमेल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

कभी पीछे न हटें: महिलाएं समान अधिकारों के लिए बढ़े आगे

सदियों से, महिलाएं समान अधिकारों, अवसरों और स्वतंत्रता के लिए लड़ती रही हैं। मताधिकारवादियों से लेकर डिजिटल कार्यकर्ताओं तक, प्रत्येक पीढ़ी ने सीमाओं को आगे बढ़ाया है, बाधाओं को तोड़ा है और पीछे हटने से इनकार किया है। हर नीति परिवर्तन और कानूनी जीत के पीछे निडर नारीवादियों ने संगठित होकर, विरोध प्रदर्शन करके और कार्रवाई की मांग करके काम किया है।

14

अब गांव-गांव में है ना बिजली, पानी 18

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बस्तर के सुदूर गांवों में विकास की गति तेज करने राज्य शासन द्वारा शुरू की गई नियद नेल्ला नार योजना से दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ रहा है।

महिलाओं को मिली ताकत, हर क्षेत्र में उत्थान 24

छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर 2023 को विष्णु देव साय सरकार के शपथ ग्रहण से लेकर अब तक 15 लाख 31 हजार 857 महिलाओं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

बस्तर में घना हुआ जंगल 27

बस्तर में वन आवरण घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो हाल ही में प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट के आंकड़ों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

विश्व में फैल रही है राजिम कुंभ कल्प की ख्याति 30

राजिम में आयोजित कुंभ कल्प के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजिम कुंभ कल्प आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है।

उद्योगों को मिली संजीवनी 32

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उनकी सरकार ने 'नई उद्योग नीति' की घोषणा की है.

ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की आप कर सकते हैं शिकायत, जानें क्या है एम परिवहन ऐप में सिटीजन सेंटिनल फीचर 36

छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्ती से कार्रवाई होगी। अब नियम तोड़ने वालों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी।

बजटः अब ट्रिपल इंजन होगा रेस,
सर्वव्यापी रणनीतियां से सबकुछ होगा आसान

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

एक तरफ बजट की शुरूआत वित्तमंत्री ओपी चौधरी उभरते युवा आशुतोष की लिखी पक्तियों से की। तभी से ऐसा लगने लगा था कि बजट शानदान प्रस्तुत होने वाला है। बजट में गहराईयां भी होगी और बजट सर्वव्यापी भी होगा। हुआ भी वहीं। गति पर आधारित बजट से डबल इंजन की सरकार को नई रफ्तार मिलने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक का रिकॉर्ड बजट एक लाख 65 हजार करोड़ रूपए का है। इस बजट की खासियत से भी हर कोई रूबरू हैं, जैसे कि बजट को वित्तमंत्री ने खुद तीन से चार रात जागकर अपने हाथों से लिखा है। उसी बजट को विधानसभा में पढ़ा गया। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा देर तक 100 पन्नों के बजट को पढ़ा गया है। इसमें विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना भी साकार होगी और जनकल्याण के कार्य फिर से आरंभ होंगे। यह बजट पूर्व में ज्ञान पर आधारित बजट को गति भी प्रदान करेगा। हालांकि एक बात तो तय है कि जिस प्रकार विधानसभा में ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र किया गया हैं, उसे भी गति मिलेगी। इस गति से चहुमुंखी विकास का रास्ता भी खुलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदेश के उन हिस्सों पर भी फोकस किया गया हैं, जहां सरकार की पहुंच कम होती है। निश्चित तौर पर फोकस होने से उन क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार होगा। विस्तार होने से गांव की उन्नति होगी और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्यधारा से भी जुड़ेंगे।

हालांकि शिक्षा पर भी काफी बजट इस बार दिया गया है। इससे पता चलता है कि शिक्षा पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी से काम किया जाएगा। गांव, खेती, सड़क और महिलाओं की उन्नति के लिए भी विष्णु सरकार की बड़ी नीतियां है। इससे निश्चित ही ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण के संकल्प को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि केंद्र ने जिस तरह से इनकम टैक्स में राहत दी हैं, उसी तरह राज्य सरकार ने किसी भी आम जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला है। यह काबिल-ए-तारीख है। इससे निश्चित ही जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास जागेगा और उस विश्वास के साथ आगे भी कार्य करने का अवसर मिल सकेगा। इस बजट से नए संकल्पों को पूरा कर आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा।

अद्भुत इंजीनियरिंग का रहस्य समेटे घाघरा मंदिर

- **बिना जोड़ के पत्थरों से बनी रहस्यमयी संरचना**

> छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्थित घाघरा मंदिर अपने रहस्यमयी निर्माण और अनोखी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बिना किसी जोड़ने वाले पदार्थ के सिर्फ पत्थरों को संतुलित करके बनाई गई इस प्राचीन संरचना का झुका हुआ स्वरूप इसे और भी रोचक बनाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास और वास्तुकला का यह अनमोल रत्न आज भी अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है।

जिले के मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से लगभग 130 किलोमीटर दूर जनकपुर के पास स्थित इस मंदिर का रहस्य आज भी विशेषज्ञों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। सदियों पुराना यह मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं, जो बिना किसी गारा-मिट्टी या चूने के इस्तेमाल के आज भी मजबूती से खड़ा है।

घाघरा मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी निर्माण शैली है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर पत्थरों को संतुलित करके इस तरह खड़ा किया गया है कि किसी भी प्रकार की जोड़ने वाली सामग्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यह तकनीक प्राचीन भारतीय वास्तुकला के अद्भुत कौशल को दर्शाती है। इस मंदिर का झुका हुआ स्वरूप इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। माना जाता है कि किसी भूगर्भीय हलचल या भूकंप के कारण इसका झुकाव हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद सदियों से यह मंदिर अपनी मजबूती के साथ खड़ा है।

घाघरा मंदिर के निर्माण काल को लेकर विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। कुछ इतिहासकार इसे 10वीं शताब्दी का बताते हैं, तो कुछ इसे बौद्ध कालीन संरचना मानते हैं। वहीं, स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां आज भी विशेष अवसरों पर पूजा-अर्चना होती है। मंदिर के भीतर किसी भी मूर्ति का न होना इसके रहस्य को और गहरा करता है। कई स्थानीय कथाओं के अनुसार, मंदिर का निर्माण उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल का प्रमाण है।

घाघरा मंदिर केवल श्रद्धालुओं का आस्था स्थल ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी अनमोल प्रतीक है। इस अद्भुत संरचना को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक और शोधकर्ता आते हैं। पुरातत्वविदों के लिए भी यह मंदिर एक शोध का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मंदिर को उचित पहचान दी जाए, तो यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी प्रमुख कस्बा जनकपुर है, जहां से घाघरा गांव आसानी से पहुंचा जा सकता है। मनेंद्रगढ़ से यहां तक का सफर लगभग 130 किलोमीटर का है। सड़क मार्ग के जरिए इस यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लिया जा सकता है।

बजट 2025-26

ज्ञान से गति की ओर

• वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 होने की उम्मीद है, जिसमें 9% से अधिक की वृद्धि है

> हमने सूत्रवाक्य रखा, ज्ञान से गति की ओर, पिछले बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के लिए फोकस रखा था, अब इन्हें आगे बढ़ाने गति अर्थात सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी, तकनीक और औद्योगिक विकास पर जोर होगा।

अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल निर्माण वर्ष के अनुरूप पूंजीगत व्यय पर 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक का हमने रखा बजट, नदियों को जोड़ना उनका था सपना, इसे साकार करेंगे। युवाओं के लिए उद्यम और रोजगार के नए अवसर खोलने वाला बजट, हाइटेक खेती की जरूरतों को पूरा करने पूरा ध्यान रखा गया. ये बाते बजट के बाद सीएम साय ने कहीं है. यह बजट वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में विकसित छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को तीव्र गति मिलेगी। इसमें धान के कटोरे की चमक "कृषि अर्थव्यवस्था" को संवारने के उपायों के साथ ही इंडस्ट्रियल हब और आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ को तैयार करने की ठोस नींव रखी गई है।

वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करने से पहले भाजपा नेता आशुतोष दुबे की पंक्तियों से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की बजट भाषण की शुरुआत

कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय
तो तुम वीर नारायण-गुण्डाधुर की तलवार लिख देना,
कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना,
कोई जो पूछे राम-राम का पर्याय तो तुम छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना,
कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना..

GATI पर आधारित है बजट

पिछले वर्ष का बजट "GYAN" (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, इस बजट का उद्देश्य "GYAN" के लिए "GATI" के माध्यम से आगे बढ़ाना है ताकि इस वर्ष राज्य को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाया जा सके और 2030 के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सके।

"GATI" का अर्थ है :

G - गुड गवर्नेंस

A - एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

T - टेक्नोलॉजी

I - इंडस्ट्रियल ग्रोथ

छत्तीसगढ़ में पहली बार 100 पृष्ठों का हस्तलिखित बजट

छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों की है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है।

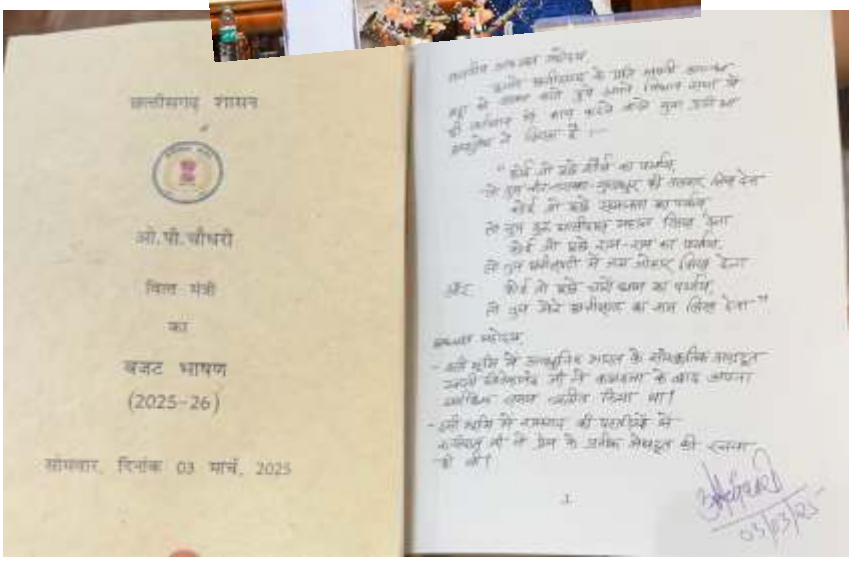

नई परंपरा की शुरुआत

अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर-टाइप्ड बजट ही पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

जानें किस योजनाओं के लिए कितना मिला बजट

- **कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये**

- **महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये**

- **5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये**

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये**

- **मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये**

- **आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये**

- सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये

- राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये

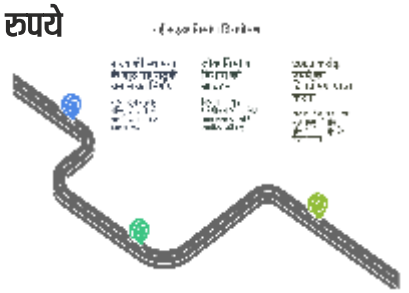

- नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये

- प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।

- नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये

- जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। अटल सिंचाई

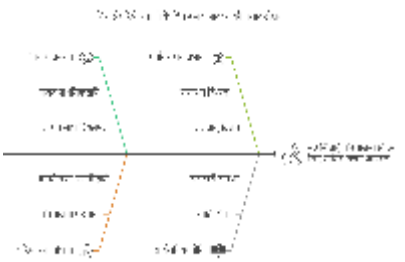

- योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।

- मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।

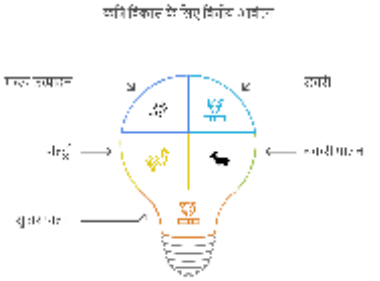

- तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान

- तेन्दूपत्ता संग्राहकों को "चरण पादुका" प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये।

- मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि।

- 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी

- 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।

- बलौदा बाजार - भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।

- कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।

- नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये।

- नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये।

- स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।

- रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- सरोंना रायपुर और जनकपुर - मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर - बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)।

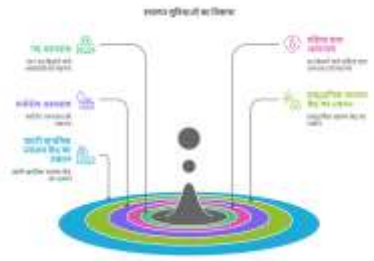

- बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।

बजट में नई पहल

- मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना ,बस्तर एवं सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ के माध्यम से प्रावधान।
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना – ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान ,उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम
- होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।
- 500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा।
- केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान।
- नगर निगमों के डी.पी.आर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये।
- राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण।
- महानदी – इंद्रावती और सिकासर – कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण।
- नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना।
- नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना।
- नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।
- सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान।
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना की जाएगी।
- नया रायपुर में 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस–वाइल्डलाइफ–वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान।
- राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर–दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्वेक्षण शामिल है।
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चौप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान।
- पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी।
- नवा रायपुर में चौंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान।
- डी.एम.एफ के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण।
- विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।
- भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान।

बजट में महत्वपूर्ण मुख्य बाते

- पूंजीगत व्यय बढ़ाने को महत्व।
- कुनकुरी जिला जशपुर में नया मेडिकल कॉलेज।
- रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाई जाएगी, इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती का पहला चरण।
- पिछले वर्ष की तुलना में उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक।
- बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति।
- रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान ।
- आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण।
- गरीब नि:संतान दंपतियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में ए.आर. टी. (IVF) सुविधा।
- सरकारी अस्पताल में एम.आर.आई, सी.टी स्कैन मशीनों के लिए प्रावधान ।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) की मदद से राज्य में डेयरी को बढ़ावा देना।

- बलरामपुर और राजनांदगांव में नया प्रयास संस्थान।
- बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर, बस्तर मैराथन,नया रायपुर मे गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए प्रावधान।
- पी.एम सूर्यघर योजना के लिए प्रावधान।
- पी.एम कुसुम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
- सी.आई.एस.एफ की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एस.आई.एस.एफ) का गठन।
- सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की भविष्य की देनदारियों के लिए पेंशन फंड बनाने के लिए प्रावधान।
- छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता कोष की स्थापना।
- सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. /53%

एक्स पर नंबर 1 में किया ट्रेंड

छत्तीसगढ़ का बजट एक्स पर ट्रेंड में पहले स्थान पर रहा। कुछ देर में ही इस संबंध में 6 हजार 196 पोस्ट किये जा चुके थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने इस बजट का थीम ज्ञान के लिए गति रखा था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन वर्गों पर फोकस कर बनाई जा रही कल्याणकारी नीतियों पर आधारित था। इस बार ज्ञान के लिए गति थीम रखा गया। यहां गति से तात्पर्य था। जी अर्थात गुड गवर्नेंस, ए अर्थात एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी अर्थात टेक्नालाजी एवं आई अर्थात इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। इसी पर आधारित रुब्ळऋ की ऋ प्रळ।ज्ञ्ऋ का ऋ बजट ने आज एक्स पर ट्रेंड किया। इस बजट में विशेष रूप से डिजिटल टेक्नालाजी पर अत्याधिक जोर होने की वजह से युवाओं को इसने काफी प्रभावित किया। इसी के साथ रुब्ळऋबजट टापिक ने भी एक्स पर काफी ट्रेंड किया।

10 नवीन योजनाओ की घोषणा

- मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना
- मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना
- मुख्यमंत्री बाय पास एवं रिंग रोड निर्माण योजना
- मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना
- मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप
- सियान केयर योजना
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
- अटल सिचाई योजना
- एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन
- राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना

चैम्पियनों के चैम्पियन रचा भारत ने स्वर्णिम इतिहास

भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया. रोहित शर्मा फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, जबकि न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र को पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला. भारत ने इस जीत के साथ इतिहास रच दिया.

भारत का यह सातवां ICC टाइटल है. साल 2013 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था. साथ ही भारत ने 2002 (संयुक्त विजेता) में विजेता रहा था. साल 2017 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर पहली बार यह ट्रॉफी जीती. अब 2025 का फाइनल भारत ने जीतकर तीसरी बार चैम्पियंस ट्रॉफी का विजेता बना. आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 1998 से खेली जा रही है और अब तक कई देशों ने इसे जीता है. भारत ने 2002 (संयुक्त विजेता) और 2013 में यह खिताब अपने नाम किया. अब 2025 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा है, जहां भारत के पास तीसरी बार ट्रॉफी जीतने का मौका है.

पाकिस्तान से छीना ताज

पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में बतौर डिफेंडिंग चैम्पियन उतरा था लेकिन अब ये खिताब उससे छिन गया है. पहले तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया और अब भारत ने फाइनल जीतकर उसके जख्मों पर नमक रगड़ा है. दरअसल साल 2017 में पाकिस्तान की टीम ने भारत को ही फाइनल में हराया था लेकिन अब भारत ने फाइनल जीत चौंपियनों के चैम्पियन का खिताब अपने नाम कर लिया है.

पाकिस्तान नहीं कर पाया फुल मेजबानी

इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई ने करारा झटका दिया था. पाकिस्तान अपने ही घर पर चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने पर अड़ा हुआ था. लेकिन बीसीसीआई के आगे उसे झुकना पड़ा. चैम्पियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ. टीम इंडिया ने अपने सभी मैच दुबई में खेले और वो अंत में चैम्पियन भी बनी. बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अपने दो स्टेडियमों पर करोड़ों रुपये खर्च किए थे लेकिन इस टूर्नामेंट में उसे परफॉर्मेंस के नाम पर ठेंगा ही मिला.

भारत की प्लेइंग 11: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11: विल यंग, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जेमिसन, विलियम ओ'रोर्के, नाथन स्मिथ।

पिच को लेकर रोहित शर्मा ने क्या कहा?

पिच को लेकर भारतीय कप्तान ने कहा, 'इसमें बहुत बदलाव नहीं आया है, हमने लक्ष्य का पीछा किया है और जीत भी हासिल की है। इससे आपको बहुत आत्मविश्वास मिलता है, खेल से टॉस दूर हो जाता है। दिन के अंत में, जो मायने रखता है वह यह है कि आप कितना अच्छा खेलना चाहते हैं। हमने ड्रेसिंग रूम में यही बात कही है, टॉस की चिंता न करें और बस अच्छा खेलें, यही हमने किया है और हमें आज भी यही करना है।' रोहित ने न्यूजीलैंड की टीम पर बातकरते हुए कहा, ' पिछले कई सालों से न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी टीम रही है, वे आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हमारे लिए चुनौती अब उनके खिलाफ अच्छा खेलना है। हमारे लिए भी यही टीम है।

राहुल की भूमिका बदली

केएल राहुल के चयन पर बहुत सवाल उठ रहे थे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के अपने पुराने साथी को उन्होंने नई भूमिका दी। उन्हें छठे नंबर पर फिनिशर का रोल दिया

जबकि वह एंकर के रोल के लिए जाने जाते हैं। 2023 विश्व कप के फाइनल में धीमी पारी खेलकर भारत की हार का कारण बने राहुल इस टूर्नामेंट में हीरो बनकर उभरे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में फिनिशर के तौर पर लंबे लंबे छक्के मारे और फाइनल सहित कई मैचों में नाबाद रहकर टीम को जीत दिलाई।

गंभीर की तैयारी का रोहित को मिला फायदा

यही नहीं हार्दिक को सातवें नंबर का रोल दिया गया जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान के अंदर जिस तरह गेंदबाजों का सुंदर प्रयोग किया उसे बाहर बैठकर कोच गंभीर ने तैयार किया। जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड से और आस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारी तो उनकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई।

ट्रोल हुए फिर भी जीता खिताब

भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक के रूप में ड्रीम इलेवन से करार है। अधिकतर बड़े खिलाड़ी फेंटेसी लीग का विज्ञापन करते है लेकिन जब गौतम ने फाइनल मुकाबले से पहले एक फेंटेसी लीग एप को लेकर पोस्ट किया तो उन्हें ट्रोल किया गया। इसके बावजूद जब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जब भारतीय टीम ट्रॉफी हाथ में उठाए थी तब गंभीर चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे थे। गंभीर का बतौर कोच यह पहला आईसीसी खिताब है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

कभी पीछे न हटें: महिलाएं समान अधिकारों के लिए बढ़े आगे

> सदियों से, महिलाएं समान अधिकारों, अवसरों और स्वतंत्रता के लिए लड़ती रही हैं। मताधिकारवादियों से लेकर डिजिटल कार्यकर्ताओं तक, प्रत्येक पीढ़ी ने सीमाओं को आगे बढ़ाया है, बाधाओं को तोड़ा है और पीछे हटने से इनकार किया है। हर नीति परिवर्तन और कानूनी जीत के पीछे निडर नारीवादियों ने संगठित होकर, विरोध प्रदर्शन करके और कार्रवाई की मांग करके काम किया है।

आज दुनिया महिलाओं और लड़कियों के लिए पहले से कहीं ज्यादा समान है – लेकिन प्रगति अभी भी बहुत धीमी, बहुत कमजोर और बहुत असमान है। हर 10 मिनट में, एक महिला की उसके ही परिवार के किसी सदस्य द्वारा हत्या कर दी जाती है। श्रम बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दशकों से अपरिवर्तित रहा है। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं और लड़कियों का योगदान सबसे कम है और फिर भी वे सबसे बुरे परिणामों को झेलती हैं। और इस गति से, आज जन्म लेने वाली लड़की को संसद में पुरुषों के बराबर सीटें मिलने में 40 साल लगेंगे। 1995 में, विश्व नेताओं ने बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई के लिए मंच के साथ लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्धता जताई , जो एक अभूतपूर्व योजना थी जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए साहसिक लक्ष्य निर्धारित किए। दो दशक बाद, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ने 2030 की समय सीमा के साथ उस प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

यहां छह कार्य जो वास्तविक अंतर ला सकते है

1. सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए - एक डिजिटल क्रांति

डिजिटल लैंगिक विभाजन को समाप्त करने से अगले पांच वर्षों में 500 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है । प्रौद्योगिकी को समानता के लिए एक बल होना चाहिए, न कि बहिष्कार के लिए। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का समर्थन करें और ऐसी नीतियां बनाएं जो डिजिटल लैंगिक विभाजन को पाटें, जिससे प्रौद्योगिकी में सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए समान पहुंच और नेतृत्व सुनिश्चित हो ।

2. सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए - गरीबी से मुक्ति

लगभग दस में से एक महिला अत्यधिक गरीबी में रहती है। सार्वजनिक सेवाएँ और सामाजिक सुरक्षा महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों और सुरक्षा का विस्तार करती हैं। महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कम से कम दुगुना अवैतनिक देखभाल कार्य भी करती हैं । देखभाल सभी समाजों की रीढ़ है, और फिर भी इसे बड़े पैमाने पर कम आंका जाता है और इसका भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसा होना जरूरी नहीं है – देखभाल के अंतर को पाटने से 2035 तक 300 मिलियन नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं । महिलाओं को समृद्ध होने और गरीबी से लड़ने का समान अवसर देने के लिए सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं, विशेष रूप से देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बजट में निवेश करें।

3. सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए - शून्य हिंसा

तीन में से एक महिला अपने जीवनकाल में हिंसा का अनुभव करती है। हालाँकि वैश्विक स्तर पर हमारे पास कई कानून हैं, लेकिन उन्हें अक्सर खराब तरीके से लागू किया जाता है और रोकथाम रणनीतियों में निवेश की कमी होती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति शून्य दंडात्मकता का संकेत देने वाले राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों को अपनाएँ, लागू करें और वित्तपोषित करें और स्थानीय महिला संगठनों का समर्थन करें।

4. सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए - पूर्ण और समान निर्णय लेने की शक्ति

दुनिया भर में, महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय अभी भी पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं । यह सिर्फ अन्यायपूर्ण ही नहीं है – यह अक्षम भी है। राजनीति, व्यापार और संस्थानों में निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कानून और नीतियाँ लागू करें, अस्थायी विशेष उपाय लागू करें।

5. सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए - शांति और सुरक्षा

600 मिलियन से ज्यादा महिलाएँ और लड़कियाँ सशस्त्र संघर्ष के नजदीक रहती हैं , और संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा में पिछले साल ही 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिला संगठन संकटों के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले और शांति के चौंपियन होते हैं। फिर भी उन्हें कम धन मिलता है और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता। शांति और सुरक्षा के सभी पहलुओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह से वित्तपोषित राष्ट्रीय योजनाएँ अपनाएँ और संकटों और संघर्ष स्थितियों में महिला संगठनों को वित्तपोषित करें।

6. सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए - जलवायु न्याय

जलवायु संकट और जैव विविधता की हानि के बढ़ने के साथ-साथ, महिलाएँ और लड़कियाँ – खास तौर पर ग्रामीण और स्वदेशी समुदायों में – इसके विनाशकारी प्रभावों का खामियाजा भुगत रही हैं। वे समाधान के मामले में भी सबसे आगे हैं। देखभाल, टिकाऊ कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे हरित नौकरियों में निवेश और उनकी पहुँच बढ़ाकर जलवायु कार्रवाई में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और नेतृत्व को प्राथमिकता दें।

महिला अधिकारों पर प्रगति

- प्रगति को जानने और उसके लिए आगे बढ़ने में ही आशा है।
- आज 89 प्रतिशत सरकारों के लिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा 193 देशों ने इसके विरुद्ध कानूनी उपाय किए हैं।
- आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू हिंसा कानून वाले देशों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले कम हुए हैं।
- दुनिया के ज्यादातर देश शिक्षा के मामले में समानता पर पहुँच चुके हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुँचने और उसे आकार देने में लैंगिक अंतर को पाटकर, हम समान अवसरों के लिए बची हुई बाधाओं को दूर कर सकते हैं और ऐसी प्रौद्योगिकी बना सकते हैं जो ज्यादा लोगों और ग्रह की सेवा कर सके।
- अधिकाधिक राज्यों ने देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ किया है और विश्व स्तर पर 32 प्रतिशत देश अब देखभाल कर्मियों के लिए बेहतर वेतन और सुरक्षित कार्य स्थितियों को बढ़ावा दे रहे हैं।
- दुनिया में 112 देश हैं जिनके पास शांति और सुरक्षा प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल करने की राष्ट्रीय योजना है – जो 2010 के 19 देशों से उल्लेखनीय वृद्धि है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ऐतिहासिक पहल

छत्तीसगढ़ की जनता बनी महाकुंभ की साक्षी

50 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुम्भ नगरी में स्थित छत्तीसगढ़ पैवेलियन में रूककर बनाया सार्थक

"आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुम्भ 2025 का आयोजन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु वहां जाएं। आप को वहां जाकर रूकने और खाने की चिंता नहीं करनी है। आपके लिए हमारी सरकार ने प्रयागराज के सेक्टर 6 में साढ़े चार एकड़ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन बनाया है। वहां पर आपके रूकने और खाने की नि:शुल्क व्यवस्था की है।"

यह कथन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महाकुम्भ 2025 शुरू होने के पहले अपने सार्वजनिक संबोधनों में कई जगह कही थी। मुख्यमंत्री श्री साय राज्य की जनता की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री श्री साय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से बात की और प्रयागराज स्थित कुंभ मेला क्षेत्र में साढ़े चार एकड़ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन का निर्माण कराया और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने खर्च पर 45 दिनों तक राज्य के श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था की।

इन 45 दिनों में छत्तीसगढ़ के लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं ने चिंतामुक्त होकर महाकुम्भ 2025 के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 45 दिनों तक चलने वाला आस्था और परंपरा का विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार अब समाप्त हो चुका है,

लेकिन जाते हुए भी ये छत्तीसगढ़ की जनता को अविस्मरणीय यादें दे गया है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भी शामिल हैं।

ऐसा नहीं है कि प्रयागराज के मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में स्थित छत्तीसगढ़ पैवेलियन सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ही था, बल्कि ये देश विदेश के सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र था। छत्तीसगढ़ पैवेलियन में लगी प्रदर्शनी को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक और श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहता था। एक तरफ जहां अन्य राज्यों के पैवेलियन रात 8 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे, छत्तीसगढ़ पैवेलियन का सांस्कृतिक कार्यक्रम रात 10 बजे तक लोगों का मनोरंजन करता रहता था। छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों ने प्रयागराज में महाकुम्भ की धरती पर ऐसा समां बांधा था कि भाषा और संस्कृति के आवरण से दूर देश के हर राज्य के लोग इसे देखने और सुनने को आतुर दिखते थे।

छत्तीसगढ़ पैवेलियन का प्रवेश द्वार बस्तर की पहचान गौर मुकुट से सुशोभित था। ये दूर से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। भीतर प्रवेश करते ही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा छत्तीसगढ़ की ममतामयी पहचान को परिलक्षित करती थी। इसके साथ ही राज्य की चार ईष्ट देवियों (मां महामाया, मां दंतेश्वरी, मां बम्लेश्वरी और मां चंद्रहासिनी) की तस्वीरों के आगे लोगों के सिर श्रद्धा से झुक जाते थे। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की योजनाओं को जानने के लिए लोग आतुर दिखते थे। प्रदर्शनी में सिरपुर, कुतुबमीनार से ऊंचे जैतखाम, भारत का नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट वाटरफाल, आधुनिक शहर नया रायपुर के बारे मे जानकर लोग स्तब्ध रह जाते थे।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी में टेक्नालाजी का भी इस्तेमाल किया गया था। 360 डिग्री का वीडियो दिखाने वाले इमर्सिव डोम में भीतर जाने के लिए पूरे देश के लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते थे और ऐसा ही कुछ हाल वर्चुअल रियेलिटी के जरिए छत्तीसगढ़ को जानने के लिए भी था। इतना ही नहीं प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति, कला, आभूषण, रहन-सहन, खान-पान, नृत्य, पशु एवं पक्षियों को भी दर्शाया गया था जो लंबे समय तक प्रादेशिक और राष्ट्रीय मीडिया के लिए आकर्षण का विषय बने हुए थे।

अब महाकुम्भ का समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे एकता का महाकुम्भ कहकर संबोधित किया है। छत्तीसगढ़ पैवेलियन अपने आप में इसका एक बड़ा उदाहरण है जहां बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए नि:शुल्क भोजन उपलब्ध था। बिना किसी ऊंच नीच के हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म और हर संप्रदाय यहां तक की विदेशी भी आते थे और छत्तीसगढ़ को पास से जानकर आश्चर्य और रोमांच से भर जाते थे।

योगी को साय ने दिया धन्यवाद

महाकुम्भ के समापन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को महाकुम्भ के सफल आयोजन और छत्तीसगढ़ को साढ़े चार एकड़ जगह उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी पहल और समर्पित प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ के लगभग 50 हजार श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ 2025 का हिस्सा बने। इन श्रद्धालुओं की भागीदारी ने राज्य की तीन करोड़ जनता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस महान आध्यात्मिक आयोजन से जोड़ा।

छत्तीसगढ़ के संत, विद्वान और श्रद्धालु महाकुंभ के पवित्र संगम में स्नान और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का भव्य प्रदर्शन हुआ। इसके माध्यम से राज्य ने अखिल भारतीय आध्यात्मिक चेतना में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल ने छत्तीसगढ़ को महाकुंभ के वैश्विक मंच पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिससे राज्य की तीन करोड़ जनता को सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव की अनुभूति हुई। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र यात्रा बना, बल्कि राज्य की आध्यात्मिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक सशक्त माध्यम भी साबित हुआ है।

अब गांव-गांव में हैं ना बिजली, पानी

• सूरज की रोशनी से हो रहा रात में भी उजाला • मिल रहा लोगो को स्वच्छ जल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बस्तर के सुदूर गांवों में विकास की गति तेज करने राज्य शासन द्वारा शुरू की गई नियद नेल्ला नार योजना से दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ रहा है। इसके तहत स्थापित सोलर हाईमास्ट से कांकेर के माओवाद प्रभावित गांवों की रातें पहली बार रोशन हो रही है। सौर ऊर्जा से संचालित डचूल पंपों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी हो रही है। कांकेर के कोयलीबेड़ा विकासखंड के पानीडोबीर, आलपरस, जुगड़ा, गुन्दूल (मर्रांम), अलपर, हेटाड़कसा और चिलपरस गांव के चौक-चौराहों को रात में रोशन करने सोलर हाईमास्ट संयंत्रों की स्थापना की गई है। रात में उजाले की अच्छी व्यवस्था हो जाने से ग्रामीण अब वहां रात्रिकालीन बैठक और सामुदायिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस निर्बाध प्रकाश व्यवस्था से वे जंगली जानवरों से खुद को ज्यादा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। नियद नेल्ला नार से संवेदनशील और दूरस्थ माओवाद प्रभावित गांवों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर विकास को नई गति दी जा रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। सोलर डचूल पंपों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है। माओवाद प्रभावित गांवों में वृहद स्तर पर सौर संयंत्रों की स्थापना से लोगों का जीवन बदल रहा है।

दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने नियद नेल्ला नार से प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर हाईमास्ट, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए सोलर पेयजल संयंत्र, सौर सुजला योजना के तहत सिंचाई व्यवस्था और सौर ऊर्जा से संचालित उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। इन कार्यों से बस्तर के दूरस्थ और दुर्गम गांवों के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।

आश्रम परिसर भी लगा जगमगाने

कांकेर के ग्राम पानीडोबीर स्थित बालक आश्रम के अधीक्षक श्री समरथ ने बताया कि पहले आश्रम परिसर में लाइट की व्यवस्था नहीं होने से बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आश्रम परिसर में सोलर लाइट लगने से रात में उजाले की व्यवस्था हो गई है। इससे बच्चे अब रात में भी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी प्रकाश व्यवस्था से रात में सब खुद को ज्यादा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं।

सौर सुजला योजना बनी किसानों के लिए वरदान

आजादी के दशकों बाद भी परंपरागत बिजली से वंचित रहे बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा क्षेत्र के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साथ के नेतृत्व में क्रेडा विभाग द्वारा अब तक बारनवापारा क्षेत्र में 1222 किसानों के खेतों में सौर सिंचाई पम्प स्थापित किए गए हैं, जिससे अब किसान बिना किसी चिंता के सिंचाई सुविधा का लाभ उठाकर लाभकारी खेती कर रहे हैं। सौर सुजला योजना के तहत बारनवापारा क्षेत्र में 2 हार्स पावर के 03, तीन हार्स पावर के 615 और 5 हार्स पावर के 604 सोलर पम्प स्थापित किए गए हैं। यह योजना उन किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, जिनके खेतों तक बिजली नहीं पहुंची थी या जिनके पास सिंचाई के अन्य संसाधन नहीं थे। ग्राम डेबी के किसान नित्यानंद बताते हैं

कि पहले सिंचाई की सुविधा न होने के कारण उनकी सालाना आमदनी मात्र 25 से 30 हजार रुपये थी। लेकिन सोलर पम्प लगने के बाद अब वे धान के साथ सब्जियां जैसे आलू, टमाटर और बरबटी उगाकर तीन से चार गुना अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह, बंशराम चौहान, बसंत कुमार कैवर्त्य, अमरू राम, धनीराम बिंझवार और गौरी बाई दीवान सहित कई अन्य किसानों की आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

समस्या हुई समाप्त

पहले किसान नदी-नालों से डीजल पम्प के जरिए सिंचाई करते थे, जिससे उनकी आय का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च हो जाता था। लेकिन सौर सुजला योजना के तहत मात्र 24,800 रुपये में सोलर पम्प मिलने से अब उनकी यह समस्या समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ शासन किसानों को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर सौर पम्प उपलब्ध करा रही है। तीन हार्स पावर के पम्प के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के किसानों को मात्र 10,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये, सामान्य वर्ग के किसानों को 21,000 रुपये का अंशदान देना होता है, जबकि 5 हार्स पावर के पम्प के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग को 20,000 रुपये तथा सामान्य वर्ग के कृषक को 25,000 रुपये का अंशदान देना होता है।बलौदाबाजार जिले में अब तक 5198 सौर पम्प लगाए जा चुके हैं। सौर सुजला योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और क्रेडा विभाग के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। सिंचाई के लिए नदी, नाले, कुएं और नलकूप प्राथमिकता से चिन्हांकित किए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की यह योजना किसानों के लिए कम लागत में सिंचाई की बेहतर और स्थायी व्यवस्था है।

पीएम सूर्य घर योजना से मिल रही है रोशनी, हो रहा है तिहरा लाभ

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी लोगों को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना से न सिर्फ हितग्राहियों को घर रौशन हो रहे हैं बल्कि आर्थिक बचत के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। भाटापारा शहर के गोकुल नगर निवासी ऋषि अग्रवाल की मानें तो पीएम सूर्य घर योजना से उन्हें तिहरा लाभ मिल रहा है। ऋषि के अनुसार एक ओर जहां सौर ऊर्जा से घर रोशन हो रहा है वहीं दूसरी और आर्थिक बचत भी हो रही है।इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत लोगों के घरों में 3 किलोवाट का सोलर चलित बिजली कनेक्शन लग रहा है और इससे लोगों को बिजली बिल भरने से छुटकारा मिल रहा है। ऋषि का कहना है कि मुझे गर्व होता है कि मैं बिना पर्यावरण को प्रदूषित करे बिजली का उपयोग कर रहा हूं। मैं इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही सभी ने अपील करता हूं कि अपने घर में पीएम सूर्यघर योजना के तहत कनेक्शन लगवाएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान दें।

300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही 78 हजार रूपए तक की अधिकतम सब्सिडी तथा सस्ते ब्याज पर लोन भी प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और नवीन रोजगारों का सृजन होगा तथा नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। सोलर पैनल स्थापना हेतु हितग्राहियों को रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता 01 से 02 किलोवाट तथा 0 से 150 यूनिट विद्युत खपत होने पर 30 हजार से 60 हजार रूपये की राशि का अनुदान प्रदान की जाएगी। इसी तरह रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता 2 से 3 किलोवाट तथा 150 से 300 यूनिट विद्युत खपत होने पर 60 हजार से 78 हजार रूपये की अनुदान प्रदान की जाएगी। यदि रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता 03 किलोवाट है तथा 300 यूनिट से अधिक विद्युत खपतहै तो 78 हजार रूपये की अनुदान प्रदान की जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि का अंतरण किया जाएगा। योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही प्रधानमंत्री सूर्य घर डाट जीओवी डाट इन या मोबाइल में प्रधानमंत्री सूर्य घर ऐप डाउनलोड कर पंजीयन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक हितग्राही बिजली ऑफिस अथवा क्रेड़ा जिला कार्यालय में उपस्थित होकर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ अपना पंजीयन करा सकते हैं।

जब PM मोदी ने शेर के शावकों के साथ बिताये पल और पिलाया दूध

- संकटग्रस्त और लुप्तप्राय वन्यजीवों को आश्रयग्रह
- वंतारा में दुनिया के सबसे बड़ा ऐलीफेंट हॉस्पिटल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित वंतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया और वहां की विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया. वंतारा देश का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण केंद्र है, जहां 2,000 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से अधिक संरक्षित, संकटग्रस्त और लुप्तप्राय वन्यजीवों को आश्रय दिया गया है. प्रधानमंत्री ने यहां पुनर्वासित किए गए जानवरों के साथ समय बिताया और उनकी देखभाल की व्यवस्था को देखा.

प्रधानमंत्री ने वंतारा में मौजूद वाइल्डलाइफ हॉस्पिटल का भी दौरा किया, जहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस अस्पताल में एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू जैसी तकनीकों के साथ वन्यजीव एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी, डेंटिस्ट्री और आंतरिक चिकित्सा जैसे कई विभाग कार्यरत हैं. उन्होंने एमआरआई कक्ष का दौरा किया, जहां एक एशियाई शेर का एमआरआई स्कैन किया जा रहा था. इसके अलावा, उन्होंने ऑपरेशन थियेटर का भी निरीक्षण किया, जहां एक तेंदुए की जीवनरक्षक सर्जरी हो रही थी, जिसे राजमार्ग पर दुर्घटना में घायल होने के बाद बचाया गया था.

PM ने शेर के बच्चों खिलाया, दूध पिलाया

पीएम मोदी ने यहां अलग-अलग प्रजाति के शावकों को दूध पिलाया. उन्होंने जिन शावकों के साथ वक्त गुजारा, उनमें एशियाई शावक, सफेद शेर, काराकल शावक और क्लाउडेड तेंदुए के शावक शामिल हैं. पीएम मोदी जिस सफेद शेर के बच्चे को दूध पिलाते दिखे, उसकी मां को रेस्क्यू करके वनतारा में लाया गया था. काराकल शेर कभी भारत में काफी संख्या में थे, लेकिन अब दुर्लभ होते जा रहे हैं. वनतारा में काराकल शेरों के प्रजनन के बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है.

वनतारा: आशा और पुनर्जीवन की उम्मीद का अभयारण्य

एक ऐसी दुनिया जहां वन्यजीव लगातार खतरों का सामना कर रहे हैं, वनतारा उनके लिए पुनर्जीवन का एक केंद्र बनकर उभरा है। एक ऐसी जगह जहां कभी विलुप्तप्राय हो चुके जानवरों को रहने के लिए घर, देखभाल और जीवन जीने का नया मौका मिलता है। यहां बचाकर लाए गए हर शेर, बाघ और सील एक कहानी कहते हैं। कहानी नुकसान की नहीं, बल्कि पुनर्जीवन की। ये तस्वीरें केवल किसी दौरे की खींची गई फोटो मात्र नहीं हैं। ये इंसानों और प्रकृति के बीच के गहरे कनेक्शन और धरती के सबसे बेमिसाल जीवों को बचाने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती हैं।

MRI रूम और ऑपरेशन थिएटर का किया दौरा

पीएम मोदी ने अस्पताल में एमआरआई रूम का दौरा किया और एक एशियाई शेर का एमआरआई होते देखा. इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन थियेटर का भी दौरा किया, यहां एक तेंदुए की सर्जरी की जा रही थी. इस तेंदुए को हाईवे पर किसी कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसे रेस्क्यू कर वनतारा लाया गया था. इसी तरह से अन्य जगहों से रेस्क्यू करके लाए गए जानवरों को भी वनतारा में जगह मिलती है. वनतारा में खासतौर पर एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा आदि का संरक्षण किया जाता है.

पीएम मोदी ने जानवरों को देखते हुए गुजारा वक्त

वनतारा में प्रधानमंत्री मोदी ने सर्कस से रेस्क्यू किए गए गोल्डन टाइगर और 4 स्नो टाइगर्स को देखा. पीएम मोदी ने एक ओकापी को थपथपाया और चिंपैंजी से भी मिले. ओरंगुटान के साथ प्यार से खेले. इसके बाद पीएम ने एक दरियाई घोड़े को करीब से देखा.

दुर्लभ और संकटग्रस्त जीवों से मुलाकात

प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े हाथी अस्पताल का भी दौरा किया और वहां की सुविधाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने केंद्र में बचाए गए तोतों को भी आजाद किया. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वंतारा के डॉक्टरों, सहायक कर्मचारियों और वन्यजीव देखभाल में लगे कर्मचारियों से बातचीत की और उनके प्रयासों की सराहना की. उनका यह दौरा भारत के वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. वंतारा अब भारत में वन्यजीव संरक्षण और देखभाल का एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जो न केवल संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षित भविष्य देने का कार्य कर रहा है, बल्कि जैव विविधता को संरक्षित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

दुनिया के सबसे बड़ा ऐलीफेंट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया

पीएम मोदी ने एक बड़ा अजगर, दो सिर वाला अनोखा सांप, दो सिर वाला कछुआ, टैपिर, रेस्क्यू किए गए तेंदुए के शावक, विशालकाय ऊदबिलाव, बोंगो (मृग) और सील भी देखे. उन्होंने हाथियों को उनके जकूजी में देखा. इस तालाब में गठिया और पैरों की समस्याओं से पीड़ित हाथियों की हाइड्रोथेरेपी के जरिए रिकवरी में मदद होती है. पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े एलीफेंट हॉस्पिटल का कामकाज भी देखा. इस दौरान उन्होंने वनतारा केंद्र में बचाए गए तोतों को भी आजाद किया. प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों, सहायक कर्मचारियों और केंद्र में विभिन्न सुविधाओं को देखने वाले मजदूरों से भी बातचीत की.

छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति

- 3 लाख करोड़ का निवेश, चार तरह के पावर प्लांट से बनेगी अपार ऊर्जा
- छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट' में अदानी, जिंदल और एनटीपीसी समेत कई कंपनियों ने किया निवेश का ऐलान
- थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मिला निवेश प्रस्ताव
- 57,000 करोड़ की जलविद्युत परियोजनाएं, नदियों से बनेगी बिजली
- थर्मल और न्यूक्लियर पावर से भी मिलेगी छत्तीसगढ़ को ऊर्जा

छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रायपुर में हुए 'छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट' में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है. इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में यह निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो।

छत्तीसगढ़ पहले से ही 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जो देश के औसत से ज्यादा है। अब हर व्यक्ति को 2048 किलोवाट-घंटे बिजली मिल रही है, जिससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपये की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की शुरुआत होगी।

थर्मल पावर क्षेत्र में भी बड़े निवेश की घोषणा हुई है। अदानी पावर 66,720 करोड़ रुपये खर्च कर कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600-1600 मेगावाट के तीन थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। जिंदल पावर रायगढ़ में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 12,800 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जबकि सरदा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 5,300 करोड़ रुपये लगाएगी। इसके अलावा, सरकारी कंपनियां एनटीपीसी और सीएसपीजीसीएल 41,120 करोड़ रुपये की लागत से 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगी।

सौर ऊर्जा में छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। जिंदल पावर और एनटीपीसी ग्रीन मिलकर 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर 2500 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन करेंगे। इसमें डोलेसरा में 500 मेगावाट और रायगढ़ में 2000 मेगावाट के सौर प्लांट शामिल होंगे। किसानों के लिए भी खुशखबरी है। पीएम कुसुम योजना के तहत 4100 करोड़ रुपये की लागत से 675 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली मिलेगी और डीजल पंपों की जरूरत कम होगी। इसके अलावा, 57,046 करोड़ रुपये की लागत से 8700 मेगावाट क्षमता के पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। इसमें एसजेएन कोटपाली में 1800 मेगावाट और जिंदल रिन्यूएबल द्वारा 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी निवेशों के जरिए छत्तीसगढ़ जल्द ही देश के

सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल हो जाएगा। इससे उद्योगों, किसानों और आम लोगों को फायदा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

प्रमुख निवेश और योजनाएं

1. परमाणु ऊर्जा: साफ और कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए ₹80,000 करोड़ का निवेश।
2. ताप विद्युत: राज्य की ताप विद्युत क्षमता को मजबूत करने के लिए ₹1,07,840 करोड़।
3. सौर ऊर्जा: सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए ₹10,000 करोड़।
4. पीएम कुसुम योजना: किसानों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ₹4,100 करोड़।
5. पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं (PSP): ग्रिड स्थिरता के लिए ऊर्जा भंडारण में ₹57,046 करोड़।
6. क्रेडा सौर पहल: सौर ऊर्जा विस्तार के लिए ₹3,200 करोड़।
7. पीएम सूर्य योजना: राष्ट्रीय सौर छत परियोजना के तहत ₹6,000 करोड़।
8. सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा:सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा अपनाने के लिए ₹2,500 करोड़।
9. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS): ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ₹2,600 करोड़।
10. पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क: बिजली पारेषण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए ₹17,000 करोड़।
11. RDSS (वितरण क्षेत्र योजना): वितरण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ₹10,800 करोड़।

महिलाओं को मिली ताकत, हर क्षेत्र में उत्थान

> छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर 2023 को विष्णु देव साय सरकार के शपथ ग्रहण से लेकर अब तक 15 लाख 31 हजार 857 महिलाओं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। यदि आँकड़ों को देखें, तो राज्य में हर महीने औसतन 1 लाख से अधिक महिलाओं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह निरंतर जारी प्रयास राज्य की महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें चिकित्सा सेवाओं से जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आयुष्मान कार्ड पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क

योजना के तहत आयुष्मान कार्ड पंजीकरण पूर्णतः नि:शुल्क है। प्रदेशभर में सभी च्वाइस सेंटर, शासकीय अस्पतालों और निजी अनुबंधित अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध है। शासकीय कार्य दिवसों में लोग इन केंद्रों पर जाकर नि:शुल्क पंजीयन करवा सकते हैं।

स्वयं करें आयुष्मान कार्ड पंजीयनः डिजिटल माध्यम से भी सुविधा उपलब्ध

यदि कोई व्यक्ति स्वयं आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता है, तो यह भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। गूगल प्ले स्टोर पर ष्आयुष्मान भारतष एप डाउनलोड करके स्वयं कार्ड पंजीकरण किया जा सकता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर आसानी से घर बैठे पंजीयन कराना चाहते हैं।इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाते हुए पहले ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने, महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिससे वे नि:शुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। यह उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

उल्लखेनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत महिलाओं के आयुष्मान कार्ड पंजीयन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 1 करोड़ 20 लाख 65 हजार 107 महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बन चुका है।प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राशन कार्ड में परिवार का मुखिया बनाए जाने की नीति को इस योजना से भी जोड़ा है,

जिससे आयुष्मान कार्ड पंजीयन को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। राज्य के 33 जिलों में राशन कार्डधारी परिवारों की महिलाओं के आयुष्मान कार्ड पंजीयन का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएँ इस योजना के अंतर्गत नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हो रही हैं।

महिलाओं की भागीदारी 44% से अधिक, एक बड़ी उपलब्धि

राज्य में राशन कार्डधारी कुल आबादी के अनुपात में देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड पंजीयन में महिलाओं की भागीदारी 44% से अधिक हो चुकी है। यह न केवल स्वास्थ्य सेवा तक महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि यह राज्य सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं की सफलता का भी प्रमाण है। आयुष्मान कार्ड पंजीयन के बाद, पंजीकृत महिलाओं को राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच और भी सुलभ हुई है।

महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त का वितरण

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को योजना की 13वीं किश्त का भुगतान किया। उल्लेखनीय है कि 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में महतारी वंदन योजना की प्रथम किश्त विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की गई थी। अब तक 12 किश्तों में 7,838 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की माताओं-बहनों को वितरित की जा चुकी है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए ''सम्मान सुविधा प्रणाली'' का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री साय इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय भुगतान के लिए ''सम्मान सुविधा प्रणाली'' का शुभारंभ करेंगे। यह पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री स्वयं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को डिजिटल और केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से सीधे मानदेय का भुगतान करेंगे।

इस प्रणाली में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियमित उपस्थिति दर्ज होगी, जिसके आधार पर उन्हें सीधे राज्य सरकार से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यह प्रणाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान में सटीकता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगी।

छत्तीसगढ़ बनेगा 'सखी वन स्टॉप सेंटर' की मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने वाला पहला राज्य

मुख्यमंत्री श्री साय इस अवसर पर उत्पीड़ित एवं संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत वे ऑनलाइन एवं मोबाइल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगी।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री श्री साय बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पोर्टल, इंफ्रा पोर्टल तथा स्थापना पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही, बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा।

महिला सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए 'सखी वन स्टॉप सेंटर' की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन भी किया जाएगा। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन जाएगा जो सखी वन स्टॉप सेंटर के सुचारू संचालन हेतु एक निर्धारित SOP लागू करेगा।

महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को मिलेगा सम्मान

कार्यक्रम में राज्य की 32 उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, 3 सर्वश्रेष्ठ सखी वन स्टॉप सेंटर, 2 नवा बिहान योजना के महिला संरक्षण अधिकारी सहित अन्य महिला सशक्तिकरण में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।

राज्य स्तरीय महिला मड़ईः महिला उद्यमिता और स्वावलंबन का मंच

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 4 से 8 मार्च 2025 तक राज्य स्तरीय महिला मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। इस मड़ई में महिला स्व-सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं।

राज्य के विभिन्न जिलों से आईं महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं अपनी उत्पादित सामग्रियों का प्रदर्शन और विक्रय कर रही हैं। इसके साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेशभर से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और महिला समूहों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, ताकि वे महिला उद्यमिता और स्वावलंबन से जुड़े विभिन्न प्रयासों को नजदीक से देख और समझ सकें।

महिला सशक्तिकरण का महाकुंभः 50,000 से अधिक महिलाओं की सहभागिता

वृहद महतारी वंदन सम्मेलन और राज्य स्तरीय महिला मड़ई में पूरे प्रदेश से 50,000 से अधिक माताएं, बहनें और बेटियां शामिल होंगी। इस भव्य आयोजन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान और आर्थिक स्वावलंबन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है।

नारी शक्ति के सम्मान का महोत्सव

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का महोत्सव होगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए इस अवसर पर महिला समृद्धि संबंधित शासकीय योजनाओं के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।

बस्तर में घना हुआ जंगल

विरल वन का 450 वर्ग किमी क्षेत्र हुआ सघन वन में तब्दील

बस्तर में वन आवरण घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो हाल ही में प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट के आंकड़ों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा किए गए सतत प्रयासों का परिणाम है। बस्तर में वन आवरण घनत्व में वृद्धि छत्तीसगढ़ की पर्यावरण संरक्षण नीति और सतत वन प्रबंधन का परिणाम है। वन घनत्व में वृद्धि जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन और जलवायु सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । बस्तर, जो अपने घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, वन संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्राथमिक फोकस क्षेत्र रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा उपग्रह-आधारित एलआईएसएस-तीन सेंसर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बस्तर के कई क्षेत्रों में वन आवरण की श्रेणी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आईएसएफआर के अनुसार, 152 वर्ग किमी वन क्षेत्र मध्यम घने वन से बहुत घने वन में परिवर्तित हुआ है। इसके अलावा, 93 वर्ग किमी भूमि गैर-वन से खुले वन में बदली है, जबकि 156 वर्ग किमी क्षेत्र खुले वन से मध्यम घने वन में परिवर्तित हुआ है। 19 वर्ग किमी क्षेत्र ओएफ सघन वन में और 18 वर्ग किमी क्षेत्र छोटे झाड़-झाड़ियों से खुले वन में अपग्रेड हुआ है।

वन आवरण में सकारात्मक परिवर्तन

इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में भी वन आवरण में सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया है, जहां 23 वर्ग किमी मध्यम घने वन से बहुत घने वन में और 16 वर्ग किमी खुले वन से मध्यम घने वन में तब्दील हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, बीजापुर वन प्रभाग ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जहां 68 वर्ग किमी क्षेत्र खुले वन से मध्यम घने वन में और 56 वर्ग किमी क्षेत्र मध्यम घने वन से बहुत घने वन में परिवर्तित हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव ने कहा कि वन विभाग के वैज्ञानिक और सक्रिय प्रयासों के चलते वन आवरण में यह महत्वपूर्ण वृद्धि संभव हुई है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भागीदारी और रणनीतिक संरक्षण उपायों ने बस्तर के हरित परिदृश्य को सुदृढ़ किया है। वन आवरण घनत्व में यह सुधार निरंतर निगरानी, जल एवं मृदा संरक्षण, आक्रामक खरपतवार हटाने, वन-अग्नि रोकथाम रणनीतियों और समुदाय के नेतृत्व वाले वनीकरण अभियानों के कारण संभव हुआ है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और बस्तर के आदिवासी समुदायों की भागीदारी ने भी इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाषा....

सीएम बोले- अंतस को सींचती है, आत्मा को एक दूसरे से जोड़ती है

छत्तीसगढ़ी रचनाकारों की किताबें स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजी जाएंगी

> छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारे अंतस को सींचने और हमारी आत्मा को एक दूसरे से जोड़ने वाली भाषा है। हमें अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा पर गर्व है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के आठवें प्रान्तीय सम्मेलन 2025 के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर हमारे पुरखों के सपनों को साकार किया। अलग राज्य बनने के बाद अपनी महतारी की भाषा छत्तीसगढ़ी को सम्मान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब की है। यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ी में बढ़िया किताबें लिखी जा रही है। इनमें से आज भागमानी, छत्तीसगढ़ के छत्तीस भाजी, छतनार, चल उड़ रे पुचुक चिरई, एक कहानी हाना के, गंगा बारू अउ माटी के दीया सहित छत्तीसगढ़ी भाषा की 11 पुस्तकों का विमोचन किया गया। आयोग के आठवें प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार रामेश्वर वैष्णव, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र, डॉ. विनय कुमार पाठक, संचालक संस्कृति एवं राजभाषा विवेक आचार्य, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव डॉ. अभिलाषा बेहार सहित अनेक गणमान्य साहित्यकार उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा अब तक डेढ़ हजार पुस्तकों का प्रकाशन

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि हमारी भाषा, बोली का मान बढ़े, लोगों का अपनी भाषा से जुड़ाव रहे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का समृद्ध इतिहास है, हमारी यह भाषा शिलालेख में भी दर्ज है। अनेक कवि और लेखक अपनी लेखनी से छत्तीसगढ़ी को समृद्ध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा अपने गठन के बाद अब तक डेढ़ हजार पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। उन्होंने कहा प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, इस नीति में बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में भी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है। बच्चे अपनी मातृभाषा में कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन छत्तीसगढ़ी भाषा को लोकप्रिय बनाने में सफल होगा। मुख्यमंत्री साय ने साहित्यकारों के आग्रह पर छत्तीसगढ़ी रचनाकारों की किताबें स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजने की घोषणा की, ताकि स्कूली बच्चे इनका अध्ययन कर सकें।

वरिष्ठ साहित्यकारों का सम्मान

मुख्यमंत्री साय ने सम्मेलन में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. देवधर दास महंत, जिला जांजगीर, काशीपुरी कुन्दन, जिला गरियाबंद, सीताराम साहू ''श्याम'', जिला बालोद, राघवेन्द्र दुबे, जिला राजनांदगांव और डॉ. दादूलाल जोशी, जिला राजनांदगांव को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

11 किताबों का विमोचन

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में 11 साहित्यकारों की पुस्तक का विमोचन किया। इनमें देवचरन धुरी की पुस्तक ''देवचरन के कहमुकरी'', डॉ. दीनदयाल साहू की पुस्तक ''भागमानी'' (छत्तीसगढ़ी उपन्यास), मुकेश कुमार के उपन्यास ''मंजरी पाती'' (छत्तीसगढ़ी उपन्यास), कन्हैया साहू ' अमित की पुस्तक ''छत्तीसगढ़ के छत्तीस भाजी'', राजकुमार चौधरी के काव्य संग्रह ''छतनार (काव्य संग्रह)'', टीकेश्वर सिन्हा की 'गब्दीवाला' की पुस्तक ''चल उड़ रे पुचुक चिरई'', हरिशंकर प्रसाद देवांगन की पुस्तक ''एक कहानी हाना के'', मिनेश कुमार साहू की पुस्तक ''गंगा बारू'' डॉ. लूनेश कुमार वर्मा के काव्य संग्रह ''माटी के दिया'', रामनाथ साहू - गीतांजली (गुरूदेव रविन्द्रनाथ टेगोर के गीताजंली काव्य के छत्तीसगढ़ी अनुवाद) और श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की पुस्तक प्रतिज्ञा (मुंशी प्रेमचंद कृत प्रतिज्ञा के छत्तीसगढ़ी अनुवाद) शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के आठवें प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष श्री रामेश्वर वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ी समृद्ध भाषा है। अलग-अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण करने और एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। संचालक संस्कृति एवं राजभाषा श्री विवेक आचार्य ने राजभाषा आयोग के कार्यों पर प्रकाश डाला। आयोग की सचिव डॉ. अभिलाषा बेहार ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए गणमान्य साहित्यकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

विश्व में फैल रही है राजिम कुंभ कल्प की ख्याति

> मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम में आयोजित कुंभ कल्प के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजिम कुंभ कल्प आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प का आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता का महापर्व है। यहाँ माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक हजारों श्रद्धालु संगम में पुण्य स्नान करते हैं और संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प को भव्यता प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। इस आयोजन से राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने राजिम कुंभ कल्प की भव्यता को पुनः स्थापित किया है और इसे और भी भव्य स्वरूप देने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2005 में राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत हुई थी, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद और संतों का सान्निध्य निरंतर मिलता रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों में इस आयोजन में कुछ बाधाएँ आई थीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने 2023 में पुनः आशीर्वाद देकर सरकार को सशक्त बनाया, जिससे यह महाकुंभ अपने परंपरागत स्वरूप में लौटा। उन्होंने कहा कि अब 54 एकड़ भूमि में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिससे इसकी भव्यता और व्यवस्थाओं में विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस आयोजन को और अधिक सुसंगठित और भव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

श्रीरामलला दर्शन योजनाः श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक पहल

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान श्रीराम के ननिहाल में बसे रामभक्तों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 'अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना' शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाँच सौ वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है।

संस्कृति और लोककला को बढ़ावा देने के लिए प्रयास

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प में राष्ट्रीय और आंचलिक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बनाया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प मेला-स्थल को और अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाया जा रहा है। सरकार आने वाले वर्षों में मेला क्षेत्र के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प हमारी आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का पर्व है। यह आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमारी सनातन संस्कृति को जीवंत बनाए रखता है।

विदेशी पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया, भव्यता देखकर कहा - इट्स वंडरफुल

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आयोजित राजिम कुंभ कल्प अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होता जा रहा है। इस वर्ष आयोजित राजिम कुंभ कल्प में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी, जिसमें देशभर के तीर्थयात्रियों के साथ विदेशी पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। नीदरलैंड से पहली बार आए सिनिस ने कहा, ष्यहाँ की संस्कृति और लोगों की आत्मीयता ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। यह एक अद्भुत अनुभव है! वहीं, इटली से आए जुबेतो और पैट्रिसिया ने कहा कि वे भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और अलौकिक संस्कृति को करीब से देखने और समझने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, ''राजिम कुंभ कल्प भारतीय आस्था और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है, जो हमें मंत्रमुग्ध कर रहा है।''

राजिम कुंभ की भव्यता से अभिभूत विदेशी पर्यटक

नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और इटली से आए पर्यटकों ने 54 एकड़ में फैले विशाल राजिम कुंभ कल्प की भव्यता को देखकर खुशी व्यक्त की। राजीव लोचन मंदिर और त्रिवेणी संगम पर स्थित कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में उत्कीर्ण प्राचीन कलाकृतियों ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। विदेशी पर्यटक महाशिवरात्रि पर निकाली गई नागा साधुओं की शोभायात्रा में भी शामिल हुए और मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। विदेशी पर्यटकों ने राजिम कुंभ कल्प की साज-सज्जा और संत समागम क्षेत्र की भव्यता देखकर कहा-''इट्स वंडरफुल'' विदेशी सैलानियों ने नागा साधुओं द्वारा निकाली गई शोभायात्रा और अखाड़ों के शौर्य प्रदर्शन को आश्चर्य और रोमांच से देखा। संत समागम क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न संतों से आशीर्वाद लिया और नागा साधुओं के तपस्वी जीवन के बारे में जाना। पर्यटकों ने पूरे आयोजन की भव्यता को अपने कैमरों में कैद किया और मेला घूमने आए लोगों के साथ सेल्फी भी ली।

राजिम कुंभ कल्पः आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अंतरराष्ट्रीय मंच

राजिम कुंभ कल्प की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। विदेशी मेहमानों की उपस्थिति से इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल रही है, जिससे भविष्य में और अधिक पर्यटक और श्रद्धालु आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से राजिम कुंभ कल्प को एक भव्य, दिव्य और यादगार आयोजन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि सम्पूर्ण भारत की संस्कृति और आस्था की गौरवशाली पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहा है।

उद्योगों को मिली संजीवनी

• नई उद्योग नीति से स्थानीय उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन • नव उद्यमियों के लिए एक सशक्त मंच

"छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उनकी सरकार ने 'नई उद्योग नीति' की घोषणा की है, जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने और नव उद्यमियों को बेहतर अवसर देने के लिए बनाई गई है. इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 2 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे."

छत्तीसगढ़, भारत का एक समृद्ध राज्य है जो अपनी प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और रणनीतिक नीतियों के माध्यम से नव उद्यमियों के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति में सहायक हैं, बल्कि नव उद्यमियों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करते हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में फार्मा, रियल एस्टेट और आईटी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से चर्चा के

दौरान कहा कि "छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास और नव उद्यमिता के लिए अपार संभावनाओं से भरा राज्य है. यह राज्य वन, खनिज और ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध है और बिजली उत्पादन में सरप्लस राज्यों में शामिल है. इन संसाधनों के चलते यहाँ उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है. सरकार निवेशकों और नव उद्यमियों को हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है, ताकि प्रदेश में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहित किया जा सके."

नई औद्योगिक नीति 2024-30 से आएगी उद्योग स्थापना में सरलता

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करके उसे सरल और सुविधाजनक बनाना है. इस नीति के तहत ऑनलाइन आवेदन और त्वरित प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे निवेश प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनी है. इसके अतिरिक्त, 'सिंगल विंडो 2.0' प्रणाली लागू की गई है, जिससे सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ आसानी से मिल रही हैं और निवेशकों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की गई है, जिससे निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करना पहले से अधिक सरल और सुविधाजनक हो गया है. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन और त्वरित प्रोसेसिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे निवेश प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनी है. इसके अतिरिक्त, 'सिंगल विंडो 2.0' प्रणाली लागू की गई है, जिससे सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ आसानी से मिल रही हैं और निवेशकों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है."महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने 'राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28' लागू की है. इसका उद्देश्य महिलाओं की सहभागिता उद्यम में सुनिश्चित करना, उन्हें उद्यम स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना है.

औद्योगिक विकास को मिलेगा नया आयाम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मानना है कि छत्तीसगढ़ को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना आवश्यक है, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें. उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक ऐसा औद्योगिक राज्य बनाना है, जहाँ स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए. नई औद्योगिक नीति से निवेश को गति मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी."

औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार

सरकार ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई और अंबिकापुर में नए औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना बनाई है. इसके अलावा, बस्तर और सरगुजा में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकसित किए जाएंगे, जिससे इन पिछड़े इलाकों में भी औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा. राज्य सरकार "एक जिला, एक उत्पाद" (ODOP) योजना को भी सशक्त कर रही है, जिसके तहत प्रत्येक जिले की पहचान के अनुसार उद्योगों को विकसित किया जाएगा.इस योजना से न केवल पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने में भी मदद मिलेगी.

नवोदित उद्यमियों को मिलेगा बड़ा समर्थन

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्टअप और नवोदित उद्यमियों को सहायता देने के लिए "छत्तीसगढ़ स्टार्टअप मिशन" शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहतरू युवाओं और महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के

लिए विशेष अनुदान और रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में तीन नए स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे. स्टार्टअप के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा. प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा. रायपुर के एक युवा उद्यमी अभिषेक शर्मा, जो एक एग्रीटेक स्टार्टअप चला रहे हैं, ने कहा, "सरकार की नई नीति से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. हमें उम्मीद है कि इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और हमारा उद्योग जगत नए आयाम छू सकेगा."

MSME और लघु उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

छत्तीसगढ़ सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए भी कई नई योजनाएँ शुरू की हैं. सरकार का लक्ष्य 5,000 नए MSME इकाइयों की स्थापना करना है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को फायदा होगा.

सरकार ने MSME उद्यमियों के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष बनाने की घोषणा की है, जिससे छोटे उद्योगों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. सरगुजा के एक लघु उद्यमी विनोद वर्मा ने कहा, "पहले हमें बैंक से लोन मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब सरकार की इस नई योजना से हमें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा."

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को और अधिक सुलभ बनाने की योजना बनाई है. अब व्यापार शुरू करने के लिए सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन होंगी और लाइसेंस 72 घंटे के भीतर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को 5 साल तक टैक्स में छूट देने का भी फैसला किया है, जिससे नए निवेशकों को आकर्षित किया जा सके.

नए औद्योगिक पार्क से निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ की साय सरकार नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना कर रही है, जिससे उद्योगपतियों को आवश्यक बुनियादी ढाँचा और संसाधन उपलब्ध होंगे. इससे नव उद्यमियों को भी बेहतरीन वातावरण मिलेगा जिससे वे अपनी व्यावसायिक यात्रा को मजबूती से आगे बढ़ा सकेंगे. इस पहल से न केवल औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि "राज्य सरकार नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना कर रही है, जिससे उद्योगपतियों को आवश्यक बुनियादी ढाँचा और संसाधन उपलब्ध होंगे. इससे नव उद्यमियों को भी सशक्त वातावरण मिलेगा, जिससे वे अपनी व्यावसायिक यात्रा को मजबूती से आगे बढ़ा सकें. इस पहल से न केवल औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे."

औद्योगिक निवेश को लेकर सकारात्मक संवाद

मुख्यमंत्री साय ने मैनकाइंड फार्मा से गौरव चौहान, एम्बेसी रीट के सीईओ विकास खडोलिया, यूअरस्टोरी की संस्थापक श्रद्धा शर्मा और मायट्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के फाउंडर रोहित कश्यप जैसे कई प्रतिष्ठित उद्यमियों और निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि "छत्तीसगढ़ सरकार उद्यमियों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक नीति स्पष्ट, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल हैं, जिससे देश-विदेश के उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में व्यापार स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं. मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार उनके व्यापार को सफल बनाने में हरसंभव सहयोग देगी. राज्य की नई औद्योगिक पहल प्रदेश को आर्थिक प्रगति और नवाचार के नए दौर में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों की राय

छत्तीसगढ़ चौंबर ऑफ कॉमर्स के रमेश अग्रवाल का कहना है, "सरकार की नई औद्योगिक नीति से व्यापारियों को कई सुविधाएँ मिलेंगी. खासकर टैक्स में छूट और MSME के लिए रियायती ऋण जैसी योजनाएँ हमारे उद्योगों के लिए फायदेमंद होंगी" वहीं, भिलाई के एक स्टील कारोबारी अशोक गुप्ता ने कहा, "छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए माहौल पहले से ही अनुकूल था, लेकिन नई नीतियों से अब राज्य में औद्योगीकरण और तेज होगा. हमें उम्मीद है कि इससे व्यापार को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी." विष्णु देव साय सरकार की नई औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. सरकार के प्रयासों से स्टार्टअप्स, MSME, खनन, ऊर्जा, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना है.अगर इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में भारत के सबसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक राज्यों में शामिल हो सकता है. नव उद्यमियों और निवेशकों के लिए यह समय छत्तीसगढ़ में नई संभावनाओं के द्वार खोलने का सबसे उपयुक्त मौका है.

घी में कद्दू से बनाएं बर्फी

अगर आपको मीठा खाना पसंद है और आप घर पर अलग अलग तरह की रेसिपीज बनाना भी पसंद करते हैं तो एक बार कद्दू की बर्फी घर पर जरूर बनाएं। इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि अगर आप एक बार इसका स्वाद चख लिए तो हमेशा बनाया करेंगे। तो, चलिए जानते हैं कैसे बनाएं कद्दू की मिठाई.

कद्दू की मिठाई बनाने के लिए सामग्री :

कद्दु, 1/2 Kg, घी - 1 Tbsp, दूध - 1 Cup, केसर का पानी - 1-2 Tbsp, चीनी - आधा कप, तंदूरी रंग- 2 पिंच, मावा - 1 कटोरा, घी - 1 Tbsp, इलायची पाउडर - 1/4 Tsp, पिस्ता, गुलाब की पंखुड़ी और चांदी वर्क गार्निशिंग के लिए

कद्दू की मिठाई बनाने की विधि :

पहला स्टेप :

सबसे पहले आधा किलो कद्दू लें और उसे अच्छी तरह धोकर तीन भाग में काटें और फिर उसे अच्छी तरह से घिस लें। जब कद्दू घिसकर हो जाए तब गैस ऑन करें और पर कड़ाही रखें। जब कड़ाही गर्म हो जाए तब उसमें 2 चम्मच घी डालें और फिर घिस हुआ कद्दू डालें।

दूसरा स्टेप:

अब, कद्दू को मीडियम आंच पर अच्छी तरह से पकाएं। कद्दू को तब तक पकाना है जब तक कि उसका पानी जल न जाए और वह पूरी तरह से गल न जाए। इस बात का खास ध्यान रखें कि उसे लो या मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं।

तीसरा स्टेप :

जब कद्दू अच्छी तरह पक जाए तब उसमें एक चम्मच केसर का पानी और आधा कप दूध डालें। अब, एक बार फिर इसे अच्छी तरह पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें चुटकीभर तंदूरी रंग डालें ताकि कलर अच्छा आये। जब कद्दू का मिश्रण एकदम गाढ़ा हो जाए तब उसमें मावा मिलाएं और फिर से अच्छी तरह से चलाएं। जब मावा अच्छी तरह मिल जाए तो उसके पांच मिनट बाद उसमें एक चम्मच इलायची पाउडर डालें और गैस बंद कर दें।

चौथा स्टेप :

अब एक कंटेनर में इस मिश्रण को डालें और सेट करने के लिए रख दें। 4 घंटे बाद इसे निकालें। यह अच्छी तरह से सेट हो गया है, अब इसे बर्फी की तरह चाकू से काट लें और ऊपर गार्निशिंग के लिए पिस्ता, गुलाब की पंखुड़ी और चांदी वर्क लगाएं। कद्दू का बर्फी तैयार है।

ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की आप कर सकते हैं शिकायत, जानें क्या है एम परिवहन ऐप में सिटीजन सेंटिनल फीचर

छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सखती से कार्रवाई होगी। अब नियम तोड़ने वालों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि अब आम जनता भी सीधे नियम तोड़ने वालों की शिकायत कर सकेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एम-परिवहन ऐप में एक नई सुविधा जोड़ी है, जिसमें "सिटीजन सेंटिनल" (नागरिक प्रहरी) का एक ऑपशन मौजूद है। इस सुविधा के तहत कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले का वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर इन्हें ऐप में अपलोड कर सकता है। अपलोड करते समय व्यक्ति को गाड़ी का नंबर साफ दिखाना होगा या नोट करना होगा। यह वीडियो 10 मिनट के भीतर संबंधित शहर के ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ के पास पहुंच जाएगा, जहां से तुरंत गाड़ी के मालिक को ई-चालान भेजा जाएगा। ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, ट्रिपल राइडिंग वाहन चलाते वक्त मोबाइल से बात करना, नो पार्किंग में वाहन पार्क करना आदि की कर सकते है ऑन लाइन रिपोर्ट कर सकते है फोटो या वीडियो अपलोड.

चालान जमा नहीं करने पर जाना होगा कोर्ट

यदि कोई चालान नहीं जमा करेगा, तो मामला सीधे कोर्ट में चला जाएगा, जहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने इस पहल की शुरुआत दिल्ली, केरल, और ओडिशा से की है, और अब छत्तीसगढ़ भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गया है। भविष्य में इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा, जहां की पुलिस और आरटीओ को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने और उनके संख्या को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने यह सुविधा शुरू की है, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। इसलिए इसे धीरे-धीरे देशभर में लागू किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में इसे आम जनता द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

शिकायत के बाद रख सकते हैं मॉनिटरिंग

आपको बता दें कि शिकायत करने वाले नागरिक इस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत की मॉनिटरिंग स्वयं कर सकेंगे। इसमें वे जान सकेंगे कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है और जुर्माना वसूला गया या नहीं। दिल्ली पुलिस इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिकायत करने वालों को 25,000 रुपए का इनाम भी देती है, ताकि अधिक लोग इस सुविधा का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ में भी इस प्रणाली को जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे नागरिक अपनी शिकायतों का बेहतर तरीके से पता रख सकेंगे। ट्रैफिक नियमों को लागू करने में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह सुविधा एप्प में दी गई है, इससे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अधिक नियंत्रण किया जा सकता है।

अगर आप भी किसी ट्रैफिक नियम उल्लंघन की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो mParivahan app डाउनलोड करें और Citizen Sentinel फीचर का उपयोग करें।

फीचर्स को जाने

- आम नागरिक सड़क पर हो रही गड़बड़ियों की जानकारी दे सकते है।
- ट्रैफिक उल्लंघन से संबंधित सबूत (फोटो या वीडियो) सीधे ऐप पर अपलोड किया जा सकता है।
- रिपोर्ट में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर सकते हैं।
- ये जानकारी सीधे संबंधित ट्रैफिक पुलिस को भेजी जाती है, जहाँ पर सत्यापन के बाद ऑन लाइन चलानी कार्यवाही की जाती है। नागरिक की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

आलिया की इस ननद की ब्यूटी के आगे फेल हैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस

50 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद हॉट

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री का फेवरेट कपल में से एक माने जाते हैं। फिल्मी परिवार से नाता रखने वाले दोनों सुपरस्टार अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। कभी अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर तो कभी फैमिली की वजह से। आज हम आलिया की एक ऐसी ननद के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रणबीर की चचेरी बहन लगती हैं। लेकिन वह खूबसूरती के मामले में अपनी भाभी से भी दो कदम आगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं 50 की उम्र में उनकी हॉटनेस का जलवा बरकरार है, आइए जानते हैं कि वो कौन हैं।

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने शादी रचाई थी। इसके साथ ही हिंदी सिनेमा की दो बड़ी फिल्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली आपस में संबंधी बने। इस दौरान इनके परिवार में कई ऐसे सदस्य मौजूद हैं, जो सिनेमा जगत में खास मुकाम हासिल कर चुके हैं। रणबीर की एक चचेरी बहन भी हैं, जो बेहद ब्यूटीफुल हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो करीना कपूर हैं तो आप गलत हैं। वह 90 के दशक की दिग्गज अभिनेत्री रही हैं और बाद में वह फिल्म इंडस्ट्री से दूर भी हो गई थीं। चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म

करते हुए राज खोल देते हैं। दरअसल आलिया भट्ट की वो ननद कोई और नहीं बल्कि करीना की बड़ी बहन करिश्मा कपूर हैं। फिल्म कलाकार रणधीर कपूर की बेटी हैं। 50 की उम्र में भी वह हद से ज्यादा बोल्ड और खूबसूरत दिखती हैं। इसका अंदाजा आप एक्ट्रेस की इन हॉट लुक वाली तस्वीरों के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। करिश्मा अपनी सादगी और झील से आंखों के दम पर फैंस का दिल आसानी से जीत लेती थीं। इतना ही नहीं यही सिलसिला आज भी कायम है।

एक बेटी की मां हैं करिश्मा

मालूम हो कि करिश्मा कपूर ने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी रचाई थी। हालांकि 13 साल के बाद 2016 में इन दोनों का तलाक हो गया। करिश्मा की एक बेटी भी है, जिसका नाम समायरा कपूर है। सिंगल मदर के तौर पर बेटी की परवरिश कर रही हैं।

ORGALIFE®

Eat Organic, Stay Healthy

CERTIFIED ORGANIC PRODUCTS

Range of 100% Natural & Eco Friendly Products

~~140/-~~ 120/- हिमालयन पिंक सॉल्ट	~~130/-~~ 115/- आर्गेनिक गुड	~~130/-~~ 115/- आर्गेनिक गुड पाउडर	~~150/-~~ 135/- गुड चना	~~115/-~~ 94/- गुड खुरचन	~~140/-~~ 125/- गुड पान
~~140/-~~ 120/- गुड पाचक	~~175/-~~ 160/- टी मसाला	~~180/-~~ 160/- रेड राइस	~~180/-~~ 165/- ब्लैक राइस	~~125/-~~ 155/- ब्राउन राइस	~~210/-~~ 190/- रामजीरा राइस
~~160/-~~ 145/- दुबराज राइस	~~170/-~~ 155/- हर्बल सोप	~~560/-~~ 545/- नारियल तेल	~~110/-~~ 95/- लाल मिर्च पाउडर	~~720/-~~ 700/- गिर गाय A2 घी	~~175/-~~ 154/- आम का अचार
~~130/-~~ 115/- मिक्स दाल	~~125/-~~ 110/- मसूर दाल	~~110/-~~ 90/- चना दाल	~~130/-~~ 115/- मूंग दाल (बिना छिलका)	~~130/-~~ 115/- उड़द दाल (छिलका)	~~125/-~~ 110/- झुरगा
~~160/-~~ 145/- काबूली चना	~~145/-~~ 120/- राजमा जम्मू	~~110/-~~ 85/- मल्टी ग्रेन दलिया	~~140/-~~ 120/- मूंग दाल (छिलका)	~~80/-~~ 60/- सुजी	~~95/-~~ 75/- साबुत चना
~~110/-~~ 85/- गेंहू आटा	~~115/-~~ 90/- चना बेसन	~~140/-~~ 120/- उड़द दाल(बिना छिलका)	~~145/-~~ 130/- अरहर दाल	~~110/-~~ 85/- रागी फ्लोर	~~90/-~~ 77/- राइस पोहा

More Then 100+ Organic Grocery Products

Scan & Shop Now

Add.: Magneto Mall, Basement infront of Smart Bazar, Raipur (C.G.)
E-kart Shop at Spree Walks, Marine Drive, Telibandha, Raipur (C.G.)

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य
बाल अधिकार संरक्षण आयोग
द्वारा बालहित में जारी

प्रिय पालकों,

बच्चों में बढ़ता मोटापा चिंता का कारण है।

पहला काम

जंक फूड से बच्चों को दूर रखें, ताजा पौष्टिक आहार दें।

दूसरा काम

बच्चों को मोबाईल से दूर रखें, बैठे-बैठे मोबाईल देखने से मोटापा बढ़ता है।

तीसरा काम

बच्चों को खुले मैदान में दौड़ने-कूदने वाले खेलों में बहुत देर तक खेलने दें।

बच्चों को मोबाईल के मोह से बचाने के लिये 9 मंत्र अपनायें

1. बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार खिलौना दें और मोबाइल के प्रयोग को बढ़ावा न दें।
2. बच्चों के साथ बातचीत करने में समय अवश्य दें। जब भी अवसर मिले टेलीविजन बंद करें और मोबाइल अलग रखवाकर आमने-सामने हल्का-फुल्का हास्यभरा वार्तालाप करें।
3. बच्चों को घर में अधिक से अधिक शारीरिक गतिविधियों में शामिल करें, जैसे त्यौहारों पर घर की सजावट, अवकाश के दिन साफ-सफाई, दैनिक कार्यों में शामिल करना आदि ।
4. बच्चों के लिए समय सारणी बनायें और मोबाइल का उपयोग धीरे-धीरे कम करवाएँ। सामने से वार्तालाप करते समय मोबाइल को बंद करवाने की आदत डालें।
5. दिन में कम से कम एक घण्टा अन्य बच्चों के साथ बाहरी खेलकूद में देने के लिए नियत करें और बच्चों को उस समय शारीरिक एवं बाहरी खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उनका मस्तिष्क उतने समय के लिए मोबाइल से दूर होगा और वे बाहरी वातावरण के आनंद को महसूस कर सकेंगे।
6. घर के भीतर शतरंज, साँप सीढ़ी, लूडो जैसे खेलों को खेलने के लिए प्रेरित करें। उनके साथ माता-पिता भी खेलें। इस प्रकार उन्हें मनोरंजन का एक और विकल्प मिलेगा।
7. यदि बच्चे चित्रकारी, संगीत, वाद्ययंत्र बजाने, नृत्य करने, अभिनय में रुचि लेते हैं तो इसे प्रोत्साहित करें। इसके लिए उन्हें साधन उपलब्ध करायें। उनके द्वारा तैयार की गई रचनाओं की सराहना करके प्रोत्साहन दें।
8. बच्चों को प्रतिदिन हल्का व्यायाम करने को प्रोत्साहित करें।
9. माता-पिता स्वयं भी बच्चों के समक्ष मोबाइल का अत्याधिक उपयोग न करें। याद रखें कि आप उनके लिए रोलमॉडल याने आदर्श है।

RO No.: 13139/1